

अध्याय II: योजना

2004-05 में सेल द्वारा तैयार की गई कॉर्पोरेट योजना (सीपी) - 2012 चरणों में प्रत्येक संयंत्र की क्षमता वृद्धि को उल्लिखित करती है, शुरू में डी-बोटलनेकिंग (2006-07) के माध्यम से वर्तमान क्षमता की प्राप्ति द्वारा, और अंत में 2011-12 तक मुख्य निवेश के माध्यम से क्षमता बढ़ाना। कच्चा माल संचालन प्रणाली से रोलिंग मिलो तक पूर्ण उत्पादन स्रोत की क्षमता विस्तार का उद्देश्य 2005-06 में 12.84 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) के कच्चा इस्पात उत्पादन को 2012 तक 21.40 एमटीपीए तक बढ़ाना था।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि विस्तार योजना भारत में इस्पात उत्पादों के लिये पर्याप्त मांग द्वारा समर्थित थी। लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि सेल के पास क्षमता विस्तार कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिये आवश्यक निधि थी। यद्यपि सेल ने उपकरण आपूर्तिकर्ता, सिविल ठेकेदारों, परियोजना सलाहकारों की क्षमता और एमईपी के प्रभावी निष्पादन के लिए आंतरिक परियोजना प्रबंधन क्षमता का आकलन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट में चर्चा के अनुसार एमईपी को हानि हुई।

2.1 उपकरण आपूर्तिकर्ता और सिविल/संरचनात्मक ठेकेदारों की उपलब्धता

कंपनी जानती थी कि विश्व भर में, इस्पात बनाने वाले उपकरणों के लिये बहुत कम तकनीकी आपूर्तिकर्ता थे। उन्हें यह भी पता था कि क्षमता वृद्धि भारत में निजी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य देशों में भी हो रही थी। विश्व इस्पात गतिविज्ञान के अनुमानों के अनुसार, 2004 में एक बिलियन टन प्रतिवर्ष के विश्व कच्चा इस्पात का उत्पादन वर्ष 2010 तक 1.130 बिलियन टन प्रतिवर्ष को पार करना अनुमानित था। चीन ने 2010 तक कच्चे इस्पात का 80 मिलियन टन जोड़ने की योजना बनाई थी। सेल के अतिरिक्त, अन्य भारतीय इस्पात उत्पादकों ने भी 2006-07 में 56.84 एमटी के कच्चे इस्पात की अपनी धरेलू क्षमता को वर्ष 2012 में 120.87 एमटी तक बढ़ाने की योजना बनाई। इसलिये, सीमित अतिरिक्त क्षमता के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य बढ़ाने का उच्च जोखिम था। विक्रेता/ठेकेदारों की सीमित अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप निष्पादन में विलम्ब भी प्रत्याशित था। यद्यपि इस्पात मंत्रालय से विचार-विमर्श द्वारा कंपनी ने, 2005-06 में एक साथ सभी संयंत्रों में 13.83 एमटीपीए से 23.46 एमटीपीए गर्म धातु उत्पादन की क्षमता विस्तार की पूर्ण योजना

बनाना चुना (2006)। परियोजना कार्यान्वयन अवधि सीपी-2012 में उल्लिखित 2012 के प्रति, 2010 में निर्धारित समाप्ति सहित, इस्पात मंत्रालय के अनुरोध पर, दो वर्षों तक कम की गई। इस्पात बनाने के लिये उपकरण आपूर्तिकर्ता उस समय पहले से ही बहुत अधिक बुक थे और कम की गई समयावधि के अंदर सभी संयंत्र के एक साथ क्षमता निर्माण का प्रतिकूल परिणाम हुआ जैसाकि नीचे टिप्पणी की गई है।

2.1.1 ओवर बुक हुये उपकरण आपूर्तिकर्ताओं ने अपने उपकरणों के लिये अधिक मूल्य मांगा

2006-08 के दौरान निविदाकृत विभिन्न एमईपी परियोजनाओं के लिये बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मूल्य उनकी उनके लागत अनुमानों से 70 से 100 प्रतिशत तक अधिक था और प्रस्तावित एमईपी परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 77,691 करोड़ तक बढ़ी, ₹ 43,142 करोड़ की अनुमानित लागत पर कुल 80 प्रतिशत वृद्धि। इस समय, कंपनी उपकरण और सेवाओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिये चरणों में क्षमता वृद्धि योजना को चरणों में विचलित करने का निर्णय ले सकती थी। तथापि, सेल बोर्ड ने अन्य इस्पात उत्पादकों जो ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे थे की तुलना में एमईपी की सभी परियोजनाओं को जल्दी लागू करके भारतीय और वैश्विक इस्पात बाजार में उछाल के लाभ उठाने के लिए एमईपी परियोजनाओं को एक साथ लागू करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि टाटा इस्पात² ने भी दो चरणों में 5 एमटीपीए से 9.7 एमटीपीए तक अपनी उत्पादन क्षमता दो गुनी करने की योजना बनाई, शुरू में 2008 तक 5 एमटीपीए से 6.8 एमटीपीए तक और बाद में 2012 तक 9.7 एमटीपीए तक और परियोजनाएँ योजना के अनुसार चालू की गई थी।

अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा के कारण, ₹ 10556 करोड़ मूल्य के 20 ठेके एकल योग्य बोली आधार पर प्रदान किये गये थे, जो अनुमानित लागत से ₹ 2,125 करोड़ (25 प्रतिशत) अधिक थे जो सभी लक्ष्य में बदलाव और बोली मूल्य खुलने तक मूल्य वृद्धि के लिये अद्यतित किये गये थे। इसी प्रकार, ₹ 660 करोड़ मूल्य के 20 ठेके, जो लागत अनुमान से ₹ 578 करोड़ (9.6 प्रतिशत) तक अधिक थे दो योग्य बोली आधार पर प्रदान किये गये थे। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के अभाव में, आदेशित मूल्य की उपयुक्तता की लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी थी।

मंत्रालय ने कहा कि उछाल भरे भारतीय और वैश्विक इस्पात बाजार ने सभी विदेशी और सेल

² स्रोत: टाटा स्टील की वार्षिक रिपोर्ट जो सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में हैं।

सहित घरेलु स्टील उत्पादकों को फलते-फूलते बाजार से लाभ प्राप्त करने हेतु क्षमता विस्तार के लिए प्रेरित किया। तकनीक और उपकरण आपूर्तिकर्ता के साथ बैठकें और पेशकश की गईं और खुली वैश्विक निविदा एमईपी कार्यान्वयन में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये निवेदित थी। वैश्विक रूप से पर्याप्त जारी विस्तार योजना के कारण सीमित विक्रेता/ठेकेदार क्षमता ने यद्यपि प्रतिस्पर्धा को काफी कम किया। एक ही बोलीदाता के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है। बोर्ड ने भारतीय और वैश्विक इस्पात बाजार में प्रचलित उछाल का लाभ लेने का निर्णय लिया और उसके लिये उन्होंने न केवल कार्यान्वयन अवधि को दो वर्ष तक कम किया बल्कि उपकरण और अन्य कार्यों के लिये अधिक मूल्य भुगतान करना भी चुना। कंपनी को निर्धारित योजना के अनुसार ठेका देने/निविदा को अंतिम रूप देने से शुरू सभी कार्य परियोजनाओं के निष्पादन/शुरू करने तक पूर्ण हैं सुनिश्चित करने के लिये तंत्र में रखना चाहिये था। यद्यपि हमने नोट किया कि बहुत कमियां थी जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ जैसे नीचे विस्तृत है, जिसके फलस्वरूप सेल अक्टूबर 2010 तक एमईपी पूर्ण नहीं कर सका।

- योजना का समन्वय और निरीक्षण करने और परियोजनाओं के निष्पादन के लिये मई 2012 में निदेशक (परियोजना और व्यापार योजना) का नया पद सृजित किया गया। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि इस समय तक, अधिकतर एमईपी परियोजनाएँ पहले से ही आदेशित और निष्पादन के अधीन थीं;
- कंपनी ने 1986/2000 दिशानिर्देशों में अपर्याप्तता नोट करने के बाद 2010 में ही परियोजनाओं के प्रतिपादन और मूल्यांकन पर नये दिशानिर्देश बनाये। इस समय तक अधिकतर एमईपी परियोजनाएँ पहले से ही निष्पादन में थीं;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नहीं बनाई गई थी और अधिकतर मामलों में पूर्व – बोली सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था। कंपनी एमईपी परियोजनाओं के कार्य का पूर्ण कार्यक्षेत्र और पूर्ण तकनीकी विनिर्देश को अंतिम दिए बगैर ही टेंडरिंग करती रही; और

- साइट मुख्य तकनीकी ठेकों के निष्पादन के समय 'सुपुर्दगी' की स्थिति में नहीं थी और ठेकेदार को साइट देने में 11 से 53 महीनों का विलम्ब हुआ था।

2.1.2 परियोजनाओं का विलम्बन

जुलाई 2008 में एमईपी की योजना बनाते समय, कंपनी खानों की क्षमता वृद्धि के लिये आवश्यक निधि में कारक नहीं थी। यद्यपि, कंपनी ने विस्तार के बाद कच्चे माल की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिये खानों की दुरुस्ती और विकास के लिये ₹ 10,264 करोड़ निर्धारित किये (मई/जून 2009)। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये, कंपनी को उल्लिखित 1:1 के ऋण इक्विटी अनुपात के अंदर सीमित वित्तीय लचीलेपन के कारण, एमईपी का कार्यक्षेत्र ₹ 64,886 करोड़ तक और कम करना पड़ा (जून 2009)। बीएसपी, बीएसएल डीएसपी और आरएसपी के लिये योजनाबद्ध ₹ 18,375 करोड़ के मूल्य की एमईपी परियोजनाएँ हटा/आस्थगित कर दी गईं और इन परियोजनाओं पर जून 2009 तक ₹ 77.92 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

आस्थगित करने के लिये एमईपी परियोजनाओं का चयन पूर्ण रूप से तदर्थ था। कंपनी ने केवल ऐसी परियोजनाओं को आस्थगित किया जिनके लिये जून 2009 में समीक्षा के समय आदेश नहीं दिये गये थे। परिणामस्वरूप, बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आरएसपी में महत्वपूर्ण परियोजनाएँ आस्थगित हुईं और कंपनी को 18,375 करोड़ के लंबित निवेश पर ₹ 8,127 करोड़ का वार्षिक कुल लाभ छोड़ना पड़ा। एमईपी निवेशों में कुल सकल लाभ भी 26.5 से 18 प्रतिशत तक कम हुआ था जैसा नीचे तालिका 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 2: बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आरएसपी परियोजनाओं के विलम्बन के कारण अनुमानित सकल लाभ में परिवर्तन

इकाई का नाम	अनुमोदित एमईपी निवेश-जुलाई 2008	विलम्बन के बाद		विलम्बन से पूर्व सकल* लाभ जुलाई 2008	विलम्बन के बाद सकल लाभ जून 2009	सकल लाभ में कमी
		अनुमोदित निवेश-जून 2009	एमईपी निवेश			
बीएसपी	21,139	17,265	3,874	4,642	3,030	1,612
बीएसएल	15,196	6,325	8,871	3,584	528	3,056
डीएसपी	8,004	2,875	5,129	2,479	833	1,646
आरएसपी	12,313	11,812	501	4,311	2,498	1,813
कुल	56,652	38,277	18,375	15,016	6,889	8,127
अनुमोदित निवेश की प्रतिशतता के रूप में अनुमानित सकल लाभ				26.5	18.0	

*कुल बिक्री वसूली घटा निर्माण लागत

मंत्रालय ने कहा कि एमईपी के तहत कुछ पैकेज/योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय जून 2009 में सेल बोर्ड के अनुमोदन से वैश्विक आर्थिक व इस्पात परिदृश्य को देखते हुए लिया गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2008 में उन्होंने सभी एमईपी परियोजनाओं को आदेश देना चुना जो उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार अधारणीय है। विस्तारित इस्पात बनाने की क्षमता के लिये, उन्हें आबद्ध खानों से कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाना भी आवश्यक था। इसलिये उनके पास साथ ही 2007-08 में इस्पात बनाने की क्षमता के विस्तार के लिये निधि की योजना बनाते समय आबद्ध खानों के लिये ₹ 10,264 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता का कारक होना चाहिये और जून 2009 तक इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त, खनिज परियोजनाएँ जिनके लिये कंपनी ने ₹ 18,375 करोड़ के मूल्य की इस्पात बनाने की परियोजना को लंबित किया अवरूद्ध हुई। आबद्ध खान परियोजनाओं के लिये जून 2009 में निर्धारित कुल ₹ 10,264 करोड़ के प्रति, ₹ 32 करोड़ के मूल्य वाली केवल नौ खनिज परियोजनाएँ मार्च 2014 तक पूर्ण हुईं और दिसम्बर 2014 तक ₹ 925 करोड़ खर्च किये गये थे।

2.1.3 क्षमता विसंगति

कुछ एमईपी परियोजनाओं के विलम्बन ने स्थिति बना दी जहाँ एकीकृत इस्पात बनाने की आपूर्ति श्रृंखला टूट गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में परियोजनाओं के बीच क्षमता विसंगति हुई। ऐसे कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. अनुमोदित योजना (दिसम्बर 2006) के अनुसार, बीएसएल में क्षमता विस्तार, 4.36 एमटीपीए कच्चे इस्पात से 7.0 एमटीपीए बढ़ाना था और यह 3.8 एमटीपीए कच्चे इस्पात के उत्पादन के लिये अतिरिक्त एसएमएस-III कॉम्प्लेक्स के संस्थापन द्वारा प्राप्त किया जाना था। एक नई कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम)-III की विक्रय योग्य इस्पात के 1.2 एमटीपीए के उत्पादन के लिये नये एसएमएस-III से कच्चे इस्पात का प्रयोग करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त, एसएमएस-II और हॉट स्ट्रिप मिल का उन्नतीकरण प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में क्षमता के अनुकूल होना भी परिकल्पित था। ₹ 2524.04 करोड़ के नये सीआरएम-III के अधिकतर मुख्य तकनीकी पैकेज मार्च-मई 2008 के दौरान आदेश दिए गये थे जबकि एसएमएस-III संयंत्र का विलंबन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीआरएम-III क्षमता का उपयोग किया जा रहा था।

मंत्रालय ने कहा कि बीएसएल के नये सीआरएम-III की इनपुट आवश्यकता एसएमएस-I, II और हॉट स्ट्रीप मिल (एचएसएम) से उनके जारी आधुनिकीकरण और उन्नतिकरण पूर्ण होने के बाद पूर्ण की जायेगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसएमएस-II और एचएसएम का जारी उन्नतिकरण नये सीआरएम-III की एकीकृत शुरुआत से पहले पूर्ण नहीं होगा और एसएमएस-I का नवीकरण शुरुआती दौर (फरवरी 2015) में था और ठेका देने के बाद पूर्ण होने में कम से कम 30 महीने लेगा।

2. बोर्ड ने हॉट मेटल के 2.0 एमटीपीए से 4.5 एमटीपीए तक आरएसपी में क्षमता विस्तार और 1.8 एमटीपीए की नई प्लेट मिल सहित कच्चे इस्पात के उत्पादन के लिये संबंधित सुविधाएँ अनुमोदित की (मई 2007)। फीडर परियोजनाओं में प्रतिप्रवाह जैसे नई ब्लास्ट फर्नेस, एसएमएस-II के लिये नया परिवर्तन आदेश किये गये थे, लेकिन अनुप्रवाह में नई प्लेट मिल की क्षमता जून 2009 में 1.8 एमटीपीए से 1.0 एमटीपीए तक कम कर दी गई थी। इस प्रकार कमी से एसएमएस में 0.8 एमटीपीए की अप्रयुक्त क्षमता बनी।

मंत्रालय ने कहा कि आरएसपी में एसएमएस-II की 0.8 एमटीपीए अधिक क्षमता से आउटपुट बीएसएल को भेज दिया जायेगा या बेच दिया जायेगा और आने वाली नई हॉट स्ट्रीप मिल के लिये भी इनपुट उपलब्ध होगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। आरएसपी ने तैयार उत्पाद के उत्पादन के लिये एसएमएस-II के आउटपुट का उपयोग करने की योजना बनाई थी और उसे आधे रूप में बेचना नहीं था जिससे प्रतिवर्ष ₹ 32.32 करोड़ का कम अंश वसूला जायेगा। बीएसएल को एसएमएस-II से अधिक आउटपुट भेजने से किराये की लागत बढ़ी। एचएसएम में कच्चे इस्पात का प्रयोग और दो या अधिक वर्ष ले सकता है क्योंकि इस परियोजना की निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (फरवरी 2015)।

2.1.4 आबद्ध विद्युत सुविधा के संस्थापित किए बिना एसएसपी में एक नया एसएमएस संयंत्र संस्थापित किया गया

एसएसपी में संस्थापित (फरवरी 2011) 1.80 लाख टन प्रतिवर्ष स्टेनलैस स्टील स्लैब की उत्पादन क्षमता सहित नया एसएमएस संयंत्र विद्युत गहन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मार्ग का प्रयोग करता है और निरंतर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एसएसपी की पावर लोड आवश्यकता 26.5 एमवीए (विस्तार से पहले) से 95.5 एमवीए तक बढ़ी। इसका मतलब राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता है जो अनिश्चित थी। तथापि, कंपनी ने एमईपी में अपनी स्वयं की आबद्ध विद्युत सुविधा की योजना नहीं बनाई। एसएमएस के संस्थापन के बाद,

राज्य विद्युत बोर्ड ने आपूर्ति कम कर दी और बिजली खपत पर मासिक प्रतिबंध लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 411.38 करोड़ कुल लागत पर स्थापित एसएमएस की उत्पादन क्षमता अनुपयोगी रही। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि एसएसपी की उर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक 2x60 मेगावाट उर्जा संयंत्र स्थापित करने में कम्पनी की ओर से विलम्ब हुआ था।

2.2 सलाहकार की नियुक्ति

सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में कोई एक रूप नीति नहीं थी। कम्पनी ने एसएसपी में एमईपी परियोजनाओं के लिए लिमिटेड निविदा आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की थी जबकि इसके पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आरएसपी में मिल क्षेत्र से अलग) की एमईपी परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मैकॉन को नामांकन आधार पर सलाहकार³ के रूप में नियुक्त किया गया था। मैकॉन के साथ वित्तीय शर्तों को अधिकतर परामर्शी कार्य पूरा हो जाने के पश्चात अन्तिम रूप दिया गया था। सलाहकारों के कारण होने वाले विलम्ब, खराब नियोजन तथा पर्यवेक्षण एवं अत्यधिक लागत अधिवहित सहित परियोजना के किसी स्तर पर चूकों के विरुद्ध संगठन की रक्षा करने के लिए कोई दाण्डिक खंड नहीं थे। बोली आमंत्रित किये बिना सलाहकार की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मैकॉन के परियोजना प्रबंधन क्षमता की पर्याप्तता उनके एक लिखित आवश्वासन के आधार पर मानी गई थी। आईएसपी स्थल पर संरचनात्मक कार्य के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के लिए मैकॉन में कुशल पर्यवेक्षकों तथा सर्वेक्षकों की भारी कमी थी।

मंत्रालय ने बताया कि मैकॉन को लाभ मिला क्योंकि वे सेल के पिछले क्षमता विस्तारण से जुड़े थे; उन्हें पहले ही एमईपी परियोजनाओं के लिए सीपीएफआर तैयार करना सौंपा गया था तथा उनके पास ड्राईंग थी; तथा सेल संयंत्रों पर उनके कार्यालय थे। मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जा सकता है:

- खुली निविदा कम्पनी को मैकॉन तथा अन्य सलाहकारों की क्षमता का आंकलन करने का अवसर उपलब्ध करा सकती थी। कम्पनी ने एसएसपी के लिए सलाहकार के रूप

³ 16.12.2006 (बीएसएल) 17.4.2007 (बीएसपी) 30.5.2007 (आरएसपी) 3.8.2007 (डीएसपी) तथा 11.1.2006 (आईएसपी)

में लिमिटेड निविदा आधार पर मै. दस्तूर एंड क. को नियुक्त किया था जिसमें मैकान ने भी भाग लिया था तथा एसएसपी में एमईपी परियोजनाएँ सितम्बर 2010 में शुरू की गई थीं। पिछले प्रत्यायकों के भरोसे पर नामांकन आधार पर मैकान की नियुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान कार्य के लिए परियोजना प्रबन्धन उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता तथा कौशल का पुनः/ आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। 1989-1997 के दौरान सेल द्वारा कार्यान्वित पिछली क्षमता विस्तारण योजना केवल 1.4 एमटीपीए हेतु थी। मैकान ने पहले कभी इतना महत्वपूर्ण परामर्शी कार्य नहीं किया था।

- आईएसपी में मैकॉन के कार्य क्षेत्र में पूरी परियोजना प्रबन्धन सेवाएं उपलब्ध कराना भी शामिल था। आईएसपी में एमईपी परियोजनाओं को एक साथ प्रारंभ करने में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब हो गया था। मैकान तथा कम्पनी में परियोजना प्रबन्धन क्षमता इतनी त्रुटिपूर्ण थी कि कम्पनी को परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए नामांकन आधार पर दूसरा सलाहकार नियुक्त (अगस्त 2014) करना पड़ा।

सिफारिश:-

1. कंपनी मनोनयन द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति हेतु अपनी नीति का पुर्नविलोकन कर सकती है। खुली निविदा से सलाहकारों का चयन उनकी परियोजना प्रबंधन क्षमता का संरचित आंकलन करने के साथ-साथ स्पष्ट बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा।